रॉबर्ट मूलर ने विशेष वकील पद से इस्तीफा दिया, ट्रंप ने कहा – मामला बंद

वॉशिंगटन: एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान और रूस के बीच रिश्तों पर अपने दो साल की चुप्पी तोड़ते हुए विशेष वकील रॉबर्ट मूलर ने बुधवार को न्याय विभाग से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, ताकि वह ''निजी जिंदगी'' में लौट सकें. मूलर ने इस्तीफा ऐसे समय पर दिया जब ऐसी मांग की जा रही थी कि वह अपने निष्कर्षों को लेकर 'कैपिटल हिल' में गवाही दें. अटॉर्नी जनरल विलियम बार के साथ उनके असहज संबंधों की भी खबरें आ रही थीं.साल 2016 के चुनाव में रूस के दखल पर मूलर की रिपोर्ट से निपटने में बार के तौर-तरीके के कारण दोनों में खटपट की खबरें आ रही थीं.

बीते मार्च में रिपोर्ट सौंपने के बाद से मूलर न्याय विभाग के कर्मी बने हुए थे. हालांकि, न्याय विभाग ने यह नहीं कहा है कि वह इतने दिनों से क्या काम कर रहे थे. इस बीच, अपनी नियुक्ति के करीब दो साल बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में मूलर ने जोर देकर कहा कि उन्होंने ट्रंप को न्याय में अवरोध पैदा करने के अपराध से बरी नहीं किया, लेकिन किसी राष्ट्रपति को अपराध के लिए आरोपित करना ''विकल्प'' नहीं है.

मूलर ने कहा कि वह न्याय विभाग के इस विचार से बंधे हैं कि किसी राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए आरोपित नहीं किया जा सकता. रूसी दखल की अपनी जांच को लेकर पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान में मूलर ने बुधवार को कहा कि जब कोई व्यक्ति मुकदमे में अपना बचाव करने के लिए खड़ा ही नहीं हो सके तो उसे किसी संभावित अपराध के लिए आरोपित करना अनुचित होगा.

मूलर की आज की टिप्पणियां जांच को लेकर सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के निष्कर्षों से मिलती-जुलती है. मूलर की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी दखल की जांच को नियंत्रित करने की कोशिश की और उन्होंने मूलर को जांच से हटवाने की कोशिश की ताकि वह इस पूरी छानबीन में अवरोध पैदा कर सकें.

विशेष वकील मूलर ने कहा कि रूसी दखल की जांच पूरी हो जाने के कारण अब वह न्याय विभाग छोड़ रहे हैं. इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मूलर के पहले सार्वजनिक बयान में कुछ भी नया नहीं है और अब मामला ''बंद'' हो चुका है. ट्रंप ने ट्वीट किया, ''मूलर की रिपोर्ट से कुछ नहीं बदलने वाला. साक्ष्य अपर्याप्त थे और इसलिए हमारे देश में व्यक्ति निर्दोष है. मामला बंद हो चुका है. शुक्रिया.''

शपथ लेने से पहले ही पाकिस्तानी अखबार के लेख में पीएम मोदी को बताया 'निरंकुश' और 'घमंडी'

दुनिया। एक तरफ आज नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसको लेकर उथल-पुथल चल रही है। हालांकि यह उथल-पुथल वहां कोई नई नहीं है। इसको समझने के लिए 2014 का रुख करना जरूरी होगा। उस वक्त जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी तब पाकिस्तान में उन्हें कट्टर सोच वाला एक निरंकुश शासक बताया था। मीडिया में इस दौरान बढ़-चढ़कर गुजरात दंगों का भी जिक्र किया था। मीडिया डिबेट में इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर गरम था। वह सब अब फिर से पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान के नामी अखबार डॉन में आज जो लेख छपा है वह फिर से इसी उथल-पुथल की तरफ इशारा कर रहा है। इसको इब्न अब्दुर रहमान ने लिखा है। रहमान पाकिस्तान की एक जानी-मानी शख्सियत हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भारत ने अपनी सेक्युलरिज्म की छवि को दफन कर दिया है। इसमें यहां तक लिखा है कि भाजपा ने इस चुनाव में जिस रणनीति से काम किया था वह पूरे देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की नीति थी। इसमें उसको सफलता मिली है। रहमान ने इस लेख में लिखा है कि मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस लाकर इस ओर इशारा कर दिया है कि उनके लिए सेक्युलर होने की छवि केवल दिखावे भर के लिए ही है। मतदाताओं ने उन्हें इस चुनाव में प्रचंड जीत दिलाकर मोदी को अल्पसंख्यकों के प्रति निरंकुश बनने का लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने अपने इस लेख से न सिर्फ पीएम मोदी को कटघरे में लाने की कोशिश की है बल्कि सेना पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि यह जीत इस बात की तरफ इशारा है कि कश्मीर में मसले का निपटारा केवल और केवल सेना की वादी में सख्ती से ही किया जा सकता है।

उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने यह पूरा चुनाव पाकिस्तान से भारत को खतरे के मुद्दे पर लड़ा था। उनकी सरकार में दोबारा वापसी भारत के पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान से भारत के संबंधों पर जरूर असर डालेगी।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पाठ याद न करने पर अध्यापक ने छात्र को खिलाया घास, मचा बवाल

पाकिस्तान में एक अध्यापक ने छात्र को इसलिए घास खाने को कहा क्योंकि वह अपना पाठ याद करके नहीं आया था.

इस्लामाबाद: एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पाकिस्तान में एक अध्यापक ने छात्र को इसलिए घास खाने को कहा क्योंकि वह अपना पाठ याद करके नहीं आया था. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, यह मामला पंजाब प्रांत के लोधरन के फतेहपुर स्कूल का है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि सात साल के कशान को अपने सहपाठियों के सामने पाठ नहीं सुनाने पर घास खाने को मजबूर किया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कशान अपना पाठ याद नहीं कर पाता है और वह इसके बदले में घास खाता है. कशान को ऐसा करने के लिए उसका स्कूल अध्यापक कहता है, जिनकी पहचान हामिद रजा के रूप में की गई है.इस बीच, कशान के पिता मोहम्मद असगर ने बताया कि मामला दो दिन पहले का है. उन्होंने कहा, "टीचर हमारे रिश्तेदार हैं और हमने उन्हें इसके लिए माफ कर दिया है क्योंकि उन्होंने इसे मजाक में किया था." जिला पुलिस अधिकारी मलिक जमील जाफर ने हालांकि पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच करने को कहा है. उन्होंने टीचर के दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं. मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने टीचर रजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

शपथ लेने के बाद पहली विदेश यात्रा में ही PM मोदी को मिलेगा सम्मान, मालदीव की संसद को करेंगे संबोधित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मालदीव की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी आगामी यात्रा के दौरान सदन को संबोधित करने का न्योता दिया है.

माले: मालदीव की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी आगामी यात्रा के दौरान सदन को संबोधित करने का न्योता दिया है. मोदी सात-आठ जून को मालदीव की यात्रा पर जा सकते हैं. विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने बुधवार को ट्वीट किया, "मालदीव की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी आगामी मालदीव यात्रा के दौरान सदन की बैठक को संबोधित करने का न्योता दिया है."

गुरुवार को दूसरे कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करने के बाद मोदी की मालदीव की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी. समाचार पत्र एडिशन की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के स्पीकर चुने गए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मंगलवार को कहा था कि राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद सोलिह ने मोदी को मालदीव की संसद को संबोधित करने का न्योता दिया है. मोदी ने नवंबर 2018 में राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद सोलिह के शपथग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मालदीव की यात्रा की थी. इसके बाद दिसंबर में सोलिह भारत आए थे.